मध्य प्रदेश में सिंचाई बांधों का निर्माण

1885. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन लघु सिंचाई बांधों के निर्माण हेतु विश्व बैंक ने सहायता प्रदान की है :

(ख) उस सहायता से किन-किन बांधों का निर्माण शुरू किया गया और इन बांधों में से कितने पूर्ण हो गए हैं और कितने अभी तक पूरे नहीं हुए है, और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के हिरन सिंचाई संभाग के अंतर्गत डोली जलाशय के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने सहायता प्रदान की है; यदि हां, तो यह सहायता कब दी गयी थी और इस बांध का निर्माण कार्य अपूर्ण क्यों छोड़ दिया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई बांधों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

Completion of Indravati Project

1886. SHRI RAHSBIHARI BARIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the target set for the completion of multipurpose Indravati project:

(b) whether it would be completed with the pace of progress at the present;

(c) if not, the year by which the project is expected to be completed; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The hydro power and irrigation components of Upper Indravati Multipurpose Project are scheduled for completion by 1998 and 2001 respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Natural Coastal Protection Project

1887. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Beach Erosion Board has submitted natural Coastal Protection Project to solve coastal problems;

(b) if so, the steps taken to implement the project; and

(c) what are the specific proposals recommended for Tamil Nadu State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) No such project has been submitted by the Beach Erosion Board so far. However, on recommendation of Beach Erosion Board in its 23rd Meeting held in July, 1994 a project outline titled "National Coastal Protection Project" was prepared in Central Water Commission and presented in the 24th Meeting of Beach Erosion Board held on 5th-6th January, 1995. The Maritime States have been requested to prepare a detailed project report and submit it to C.W.C. for compilation as a consolidated national project.

The consolidated project proposal can be firmed up only on receipt of full details from the Maritime States.

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

1888. **श्री अजीत जोगी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक राष्ट्रीय पुनर्वास नीति तैयार कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास संबंधी किन-किन प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य किया गया है; और

(ङ) क्या प्रस्तावित नई नीति को सरदार सरोवर और नर्मदा परियोजना जैसे प्रमुख परियोजनाओं के कार्य सम्पादन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु क्रियान्वित किया जायगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) इस समय कोई भी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नहीं है । विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करना परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । तथापि, जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाने के वास्ते उपाय प्रारंभ किए गए हैं जिसके लिए विभिन्न तथ्यों और संबद्ध पहलुओं पर उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय जल बोर्ड की उप समिति द्वारा नीति का एक मसौदा तैयार किया है । राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई मसौदा नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की तीसरी बैठक की कार्यसूची में शामिल की गई है ।

(घ) परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास एक जारी प्रक्रिया है । कुछ वृहद जल संसाधन परियोजनाओं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है, में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं ऊपरी कृष्णा परियोजना (कर्नाटक), सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र) माजलगांव, भोमा, कुवाड़ी, कृष्णा, अपर पेनगंगा और नांदूर मधमेश्वर परियोजनाएं (महाराष्ट्र) बाणसागर, राजघाट, भंवर तालाब और कोलार परियोजनाएं (मध्य प्रदेश), रेंगाली एवं ऊपरी कोलाब परियोजनाएं (उड़ीसा), कुटियाडी परियोजना (केरल) और पर्च बांध परियोजना (पंजाब) ।

(ङ) इस संबंध में प्रचलित नीति के अनुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपाय क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं ।

Sardar Sarovar Project

1889. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the recent report of the Dam Safety Panel on Sardar Sarover Projec (SSP) has pointed out certain serious technical and geological problems;

(b) if so, what is the composition of this Panel and the details of the technical and geological problems detected by it and what are the main recommendations of the panel; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to overcome these technical and geological problems?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) No, Sir. All aspects of the damage to the stilling